विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 288 वर्ष – 13 **प्रकाशन सामग्री** 28 सितंबर 2013 से 12 अक्टूबर 2013

गरीबी और भूख के कुचक्र में फंसे मासूम

• बाबूलाल नागा •

एक वर्ष का दीपक महज तीन दिन बीमार रहा और चल बसा। एक वर्ष की सलोनी ने भी तीन दिन की बीमारी के बाद दम तोड़ दिया। दो वर्ष की तनिशा की जिंदगी भी दो दिन की बीमारी में ही चुक गई। दो साल की दिव्या महज पांच दिन बीमार रही और चल बसी। तीन साल की सपना भी सात दिन तक जिंदगी से लड़ाई लड़ने के बाद हार गई। बारां जिले की किशनगंज तहसील के सुवांस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सुवांस, मोयदा व करवरी कलां गांवों में कुपोषण से पिछले दो सालों में पांच बच्चों की मौत हो गई। ये पांचों सहरिया आदिवासी बच्चे अकाल कवलित हो गए और सरकार व प्रशासन इनकी मौत का कारण कुपोषण न मानकर बुखार, खांसी, खून के दस्त और स्वास्थ्य का चढ़ना वगैरह मान रहा है।

किसी ने खबर दी कि ये बच्चे कुपोषण से मर गए तो हड़कंप मच गया सरकारी मशीनरी में। मौतों को लेकर सुर्खियों में रहते आए सुवांस गांव एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। सुवांस गांव में सरकारी नुमाइंदे जा पहुंचे। पूरी राजस्थान सरकार व बारां प्रशासन पहुंच गया किशनगंज क्षेत्र के सुवांस, मोयदा व करवरी कलां गांवों में। पूरी ताकत लगा दी इन बच्चों की कुपोषण से मरने की खबरों का खंडन करने के लिए। सरकारी जांच में पाया गया कि ये बच्चे कुपोषण से नहीं मरे। परिजनों की लापरवाही की वजह से इनकी मौतें हुईं। सरकार व प्रशासन इस बात से सहमत थे कि ये बच्चे बीमारी से मरे लेकिन इसी के साथ जेहन में एक सवाल उभरना भी स्वाभाविक है कि क्या बीमारी के कारण मौतों पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये मौतें भी असाधारण मौतें तो हैं ही कुपोषण न सही, बीमारी के चलते ही सही। हर साल सैकड़ों की संख्या में सहरिया आदिवासी बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इन बच्चों के चेहरों पर भूख साफ दिखाई देती है। जन्म से ही शारीरिक कमजोरी की जकड़ में फंसे रहते हैं। सरकार इनके भूख व कुपोषण से न मरने की खबरों का खंडन कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं। निरंतर भयावह होती जा रही कुपोषण की समस्या को कोई अहमियत नहीं देते हम। बीमारी व कमजोरी के चलते मारे गए मासूम बच्चों का रिकॉर्ड तो है ही नहीं। चिकित्सा विभाग के रिकॉर्ड अनुसार कुपोषण से बारां जिले में छह साल में पांच मौतें हुई है। वह भी 2009 से 2001 में हुई है। इनमें से एक शाहाबाद न्यूट्रीशन व चार बच्चों की मृत्यु बारां न्यूट्रीशन केयर सेंटर में हुई।

बारां जिले के आदिवासी सहरिया बाहुल्य क्षेत्र में कुपोषण से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन बच्चों में कुपोषण से बचाने के सरकार के सारे प्रयास बौने साबित हो रहे हैं। जिले में अतिकुपोषित के रूप में चिंह्ति करीब आधा दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 28 हजार से अधिक बच्चे कुपोषित के रूप में चिंह्ति है। क्षेत्र में कुपोषण की समस्या व्यापक रूप में देखने को मिल रही है। करोड़ों खर्च किए जाने के बाद भी जिले में 29 प्रतिशत बच्चे कुपोषित है। अभी 0 से 5 साल का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। महिला बाल विकास एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सितंबर 2012 में कराए गए सर्वे अनुसार 30 सितंबर 2012 तक 2820 अतिकुपोषित बच्चे चिंह्ति किए गए। सर्वे अनुसार जिले में एक लाख पांच हजार 361 बच्चों में से 28 हजार 377 बच्चे कुपोषित है जबकि 74 हजार 164 बच्चे सामान्य है। सहरिया बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज व शाहाबाद में सर्वाधिक कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चे हैं। सर्वे अनुसार शाहाबाद में 3880 कुपोषित व 486 अतिकुपोषित बच्चे हैं जबकि किशनगंज में 4732 कुपोषित व 749 अतिकुपोषित बच्चे हैं। कुपोषण उपचार केंद्रों से प्राप्त आंकड़े कुछ ओर ही बयां करते हैं। सरकारी रिकॉर्ड अनुसार अगस्त 2006 से मार्च 2013 तक शाहाबाद कुपोषण उपचार केंद्र में 1675 अतिकुपोषित बच्चे भर्ती हुए। इनमें सहरिया जनजाति के 518 बच्चे शामिल हैं। कुल भर्ती हुए बच्चों में 815 लड़के व 860 लड़कियां हैं। 6 से 24 माह तक के बच्चों की संख्या 1389 हैं जबकि 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 286 हैं। कुल 92 बच्चों को जिला स्तरीय कुपोषण उपचार केंद्र रैफर करवाया गया। किशनगंज में फरवरी 2013 से कुपोषण उपचार केंद्र संचालित किया जा रहा है। मार्च 2013 तक 11 अतिकुपोषित बच्चे भर्ती हुए। केलवाड़ा कुपोषण उपचार केंद्र में मई 2011 से मार्च 2013 तक 224 अतिकुपोषित बच्चे भर्ती हुए। इनमें से 160 सहरिया जनजाति के बच्चे शामिल हैं।

सरकार सहरियाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, इसके बावजूद कुपोषण के ये भयावह आंकड़े सरकारी प्रयासों की पोल खोल रहे हैं। दूसरी तरफ जिले में कई एनजीओ काम कर रहे हैं जो सहरियाओं के विकास व कुपोषण से निपटने का दावा करते हैं। लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, अगर ठीक से मॉनिटरिंग हो तो ऐसी दिक्कत ही नहीं रहे। दरअसल, अभिभावक तो रोजी रोटी के लिए रोज काम पर निकल जाते हैं। ऐसे में बच्चों को पर्याप्त पोषाहार नहीं मिल पाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की

जारी

स्थितियां ठीक नहीं हैं। आमतौर पर कुपोषण पहले चरण में नहीं आता और लगातार भूख तथा बीमारी की हालत में बहुत तेजी से सेहत में गिरावट पैदा कर सकता है। कुपोषण से ग्रसित बच्चों का शुरुआत में ही उपचार नहीं हो पाता है, जब हालात बिगड़ जाती है तब उन्हें कुपोषण उपचार केंद्र में लाया जाता है। परिजन रोजी रोटी की समस्या के चलते वहां भी समय नहीं दे पाने से बच्चों को ले जाते हैं। घर पर भी बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। लिहाजा बच्चे कुपोषण के जाल से बाहर निकल ही नहीं पाते। **(विविधा फीचर्स)**